Urban Development Schemes for Calcutta Municipal Area

1518. SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHARI: Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the complaint that many inadequately developed schemes in the Calcutta Municipal area, like the Regent State Development Scheme of the Development Department of the Government of West Bengal, is causing great inconvenience to the local people who hold residential plots and residential buildings under these schemes;

(b) why the areas included under these development schemes have not been handed over to the Calcutta Corporation so as to provide all normal urban amenities to the people living in these areas; and

(c) the number of such development schemes in Calcutta Municipal area undertaken by the West Bengal Government which have not been taken over by the city Corporation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Ghataprabha Project Mysore

1519. SHRI M. N. NAGHNOOR: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the cost of Ghataprabha Project in Mysore and the irrigable area under this project;

(b) the amount spent so far thereon;

(c) the amount provided during the current year and proposed to the earmarked during the Fourth Fiver Year Plan; and

(d) the steps taken by Government to expedite the project?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) The Ghataprabha Project comprises two stages. The estimated cost of Stage I is Rs. 5.8 crores and the revised estimated cost of Stage II is Rs. 35 crores. The ultimate irrigation benefit for both the stages is 3 lakh acres.

(b) Stage I of the Project is almost complete. The expenditure on Stage II up to the end of March, 1968, was about Rs. 10 crores.

(c) A tentative provision of Rs. 2 crores has been made for earmarked Central loan assistance to the Government of Mysore for Stage II of the Project during the current financial year. The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised.

(d) Earmarked Central loan assistance is being given to the Government of Mysore from 1967-68 onwards to expedite the execution of the Project.

Kabini Project in Mysore

1520. SHRI M. N. MAGHNOOR: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) when the Kabini Project in Mysore was sanctioned;

(b) the cost thereof;

(c) the area under irrigation of this project; and

(d) the funds provided for early completion of the Project?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) to (c). The Kabini Project was approved in April, 1958, for an estimated cost of Rs. 2.5 crores to irrigate an area of 20,000 acres.

(d) The expenditure incurred on the project up to the end of March, 1968 was about Rs. 3.5 crores. The State Government propose to spend Rs. 70 lakhs during the current year.

चीन को अभ्रक की तस्करी

1521. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1968 के दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अभ्रक चोरी छिपे चीन भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार का ध्यान प्रश्न में उल्लिखित खबर की ओर दिलाया गया है ।

(ख) भारत से नेपाल को अभ्रक के निर्यात पर कोई रोक नहीं है । लेकिन, स्थिति पर निगाह रखी जा रही है ।

उपग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिये विदेशी ऋण

1522. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एक उपग्रह केन्द्र की स्थापना के लिये कैनेडा ने भारत को ब्याज रहित ऋण देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त ऋण से केन्द्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) उक्त ऋण कुल कितने डालर का होगा और इसे कैनेडा सरकार को कितनी किस्तों में चुकाया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). कनाडा की सरकार ने उपग्रह संचार भूमि केन्द्र (सेटेलाइट कम्यूनिकेशन अर्थ सेंटर) के लिए जिसे महाराष्ट्र राज्य में अरवी में बनाने का विचार है, कनाडा के 8 फरवरी, 1968 के 211.4 लाख कनाडियन डालरों के गैर-प्रायोजना गैर-वस्तु ऋण में से 40 लाख कनाडियन डालरों की रकम वितरित करना स्वीकार कर लिया है । 211.4 लाख कनाडियन डालरों का ऋण ब्याज मुक्त है और वह 31 मार्च, 1977 से शुरू होने वाली 80 छमाही किस्तों में 50 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है (जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है) ।

कोरोनेशन मेमोरियल, दिल्ली के निकट विदेशियों की प्रतिमाओं का लगाया जाना

1523. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरोनेशन मैमोरियल, दिल्ली के पास कुछ विदेशियों की प्रतिमाओं को पुनः लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम ने प्रतिमाओं को पुनः लगाने का विरोध किया है और इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशियों की प्रतिमाओं को लगाने का अन्तिम निर्णय अंतिम रूपेण कर लिया है और यदि हां, तो उन प्रतिमाओं की संख्या कितनी होगी तथा उन विदेशियों के नाम क्या हैं, जिनकी प्रतिमाएं कारोनेशन मैमोरियल के निकट लगाई जायेंगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां । मामला विचाराधीन है ।